वित्त मंत्री

श्री सुरेश कुमार खन्ना

का

2026-2027 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के बजट अनुमानों पर
माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2026–2027 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर,

हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो।

वर्ष 2024–2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 30.25 लाख करोड रूपये आकलित हुयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रूपये आकलित हुयी है जो वर्ष 2016–2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रूपये के दो गुने से अधिक है। वर्ष 2025–2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुये हैं। बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गयी है।

एस0डी0जी0 इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018–2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023–2024 में 18 वें स्थान पर आ गयी है।

राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है। इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है।

उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ''लीडर श्रेणी'' की रैंकिंग हासिल हुई है।

सरकार की अवस्थापना–प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड–लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है।

वर्ष 2016–2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024–2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है। फसल सघनता जो 2016–2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024–2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है।

वर्ष 2016–2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गयी।

हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

मान्यवर,

हमारा यह मानना है कि आज के युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश में नयी और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जायेगी।

प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेन्टर क्लस्टर्स की स्थापना की जायेगी। प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना तथा टेक युवा–समर्थ युवा योजना लाई जा रही है। सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिये योजनाओं के साथ–साथ त्वरित व भविष्योन्मुखी विकास हेतु आधुनिक तकनीक तथा एआई के सदुपयोग व प्रदेश में उसके विकास के लिये इको सिस्टम बनाने के लिये प्रदेश सरकार कार्य कर रही है।

प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ–साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है। मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है।

डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जायेगा। कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जायेगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। विश्व बैंक सहायतित यू.पी.एग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्री–एक्सपोर्ट हब की स्थापना करायी जायेगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जनविश्वास सिद्धान्त के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज एवं सुगम बनाया जायेगा। प्रदेश में डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना पर कार्य किया जायेगा।

मान्यवर,

जहाँ अर्थव्यवस्था में पूँजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर

प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिये सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिये युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ–साथ युवाओं के कौशल सम्वर्द्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जायेगी तथा नये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पी0पी0पी0मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेण्ट केन्द्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जाने होंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिये महिलाओं के लिये पृथक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

मान्यवर,

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026–2027 के केन्द्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 02 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के दो स्थलों–सारनाथ एवं हस्तिनापुर के विकास की योजना बजट में रखी गई है। इसके लिये मैं प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।

इसके अलावा, प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेन्सी एवं ट्रामा सेन्टर की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के हॉस्टल, 10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन, जैसी योजनाओं का लाभ अन्य प्रदेशों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्राप्त होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा डायबिटीज तथा कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी किये जाने की घोषणा की गई है। यह अत्यन्त सराहनीय कदम है।

मान्यवर,

किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

बजट पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष इस बारे में एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रस्तुत करना चाहूँगा।

किसान

- हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रूपये से अधिक के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रूपये से भी 90,802 करोड़ रूपये अधिक है।
- पेराई सत्र 2025–2026 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गयी है। इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा।
- रबी विपणन वर्ष 2025–2026 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय करते हुए 2,512 करोड रूपये का भुगतान किया गया।

- खरीफ विपणन वर्ष 2025–2026 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।
- नलकूपों से सिंचाई के लिये किसानों को दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है।
- वर्ष 2025–2026 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अन्तर्गत दिनाँक 19 दिसम्बर, 2025 तक 10,257 करोड़ रूपये का ऋण वितरण कर 15 लाख 01 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- वर्ष 2025–2026 मे दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रूपये 600 करोड़ के सापेक्ष दिनाँक 30 नवम्बर, 2025 तक 205 करोड़ रूपये का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2017–2018 से 2024–2025 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025–2026 में खरीफ के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में माह दिसम्बर, 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

महिला

- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बी0सी0 सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन–देन करते हुये लगभग 107 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया।
- महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है।
- महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है।
- सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सी.सी. टी.वी. नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नये शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये

जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

- मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है।
- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुयी हैं।

युवा

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केन्द्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है।
- युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा–सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किये जा चुके हैं।
- प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

रोजगार

- पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरूष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गयी है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी।
- पुलिस विभाग में चयनित किये गये 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।
- मिशन रोजगार के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुये अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये

सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

- निवर्तमान मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी, 2026 तक 20 करोड़ 19 लाख 62 हजार मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

श्रमिक कल्याण

- अपने घर, गाँव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिये लेबर अड्डों का निर्माण कराया जायेगा।
- एक्स–ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रूपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 01 लाख रूपये का भुगतान किया जा रहा है।
- प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया।
- रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों/श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है।

मान्यवर,

हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिये अथक परिश्रम किया है, और उनका यह संकल्प है–

'' यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है।
दिया जला के रोशनी कर दूँ, जहाँ अंधेरा है।।''

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2026–2027 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रूपये (09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रूपये) है जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में पूँजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत है। कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिये आवंटन कुल बजट का 9 प्रतिशत है।

16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत रखी गई है जो वर्ष 2030–2031 तक लागू रहेगी।

राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने पर वर्ष 2016–17 में 29.3 प्रतिशत की ऋणदृजीएसडीपी कि अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019–20 तक घटाकर 27.9 प्रतिशत कर दिया था। परंतु, कोविड–19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021–22 में 33.4 प्रतिशत हो गया।

मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप वर्ष 2024–25 में ऋणदृजीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27 प्रतिशत से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में इसे और कम कर 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

कानून व्यवस्था

- जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।
- वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिये अपहरण के मामलों में क्रमशः 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 47 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की कमी हुयी है।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शील भंग के मामलों में क्रमशः 48 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की कमी आयी है।
- अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गम्भीर चोट के मामलों में क्रमशः 43 प्रतिशत, 94 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी आयी है।
- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रूपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये 346 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अग्निशमन केन्द्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्थ, नवनिर्मित केन्द्रों को पूर्ण से क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र.भमण हेतु वाहनों के क्रय हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के लिये 14,997 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं।
- वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधाओं से आच्छादित हैं। 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पी0पी0पी0 पद्धति से की जानी है।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4,540 थी जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 1,221 थी जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया।
- 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1023 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 315 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- असाध्य रोगों के इलाज के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये 37,956 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 2025–2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई जो आंगनबाडी केन्द्रों तथा स्कूलों में जा कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनाँक 08 दिसम्बर, 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत 03 करोड़ 28 लाख 44 हजार 929 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।
- जपानी इन्सेफिलाईटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है।
- आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है।
- एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डीजिजेज एवं कोविड–19 की रिपोर्टिंग की जा रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयुष

आयुष सेवाओं के लिये लगभग 2,867 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी मेडिकल कालेज एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं।
- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 02 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में संचालित हैं जिनको सुदृढ़ करते हुये इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिये 27,103 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

- मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु 5,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण की प्रकिया गतिमान है। इस योजना हेतु 2,374 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अवस्थापना विकास हेतु 2,000 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट एवं फॉर्च्यून–500 कम्पनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति–2023 के कियान्वयन हेतु 1,000 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश एवं 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिये 3,822 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग(एम0एस0एम0ई0) उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ है। लगभग 3.11 करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का एम0एस0एम0ई0 सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है।
- प्रदेश में एम.एस.एम.ई. उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ''**सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन**'' की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिये 575 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान** हेतु 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है परन्तु आवश्यकतानुसार इसे बढाया जायेगा।
- **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 225 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''**एक जनपद एक व्यंजन**'' जो एक नई योजना है, के लिये 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिये लगभग 5,041 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में पाँच गुने से अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2026–2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
- प्रदेश में गारमेन्टिंग हब बनाने हेतु पी0एम0मित्र पार्क योजना के अन्तर्गत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करायी जा रही है।
- हथकरघा बुनकरों के साथ–साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिये अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिये 4,423 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी–2022 हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- ''मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में 800 इकाईयों को 40 करोड़ रूपये बैंक ऋण से नये उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

- पं0दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी, गोरखपुर के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिये 07 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला के परम्परागत कारीगरों के चहुँमुखी विकास हेतु संचालित माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिये 13 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

आई.टी.एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिये 2,059 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है।

- एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन का आरम्भ किया जा रहा है जिसके लिये 225 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इण्डिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आई.टी.आई. को एआई लैब के साथ ही राज्य में एआई सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस तथा इण्डिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रूपये की व्यवस्था है।
- साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिये 95 करोड़ 16 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एआई–प्रजा कार्यक्रम की शुरूआत की गई है और इस पहल में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम, और वन एम वन बी जैसी वैश्विक स्तर की कम्पनियाँ एआई प्रशिक्षण में हमारे साथ काम कर रही हैं जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों सहित राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश में 30,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं जिनमें 6 डाटा सेन्टर पार्क्स और 2 डाटा सेन्टर इकाईयाँ हैं। इससे लगभग 21,342 करोड़ रूपये का निवेश तथा 644 मेगावॉट की क्षमता अर्जित की गयी।

मान्यवर,

माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित विस्तार हो रहा है। हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के आई0टी0 हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनायेगा–

'' सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं।
डुबो देते हैं जो अपने आपको पसीने में।।''

सड़क एवं सेतु

सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौडीकरण/सुदृढ़ीकरण /निर्माण हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रूपये एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रूपये तथा सड़कों के निर्माण/ चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये 18,290 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

- सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्यगंगा स्टेज–2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बाँध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित/पुनर्स्थापित होगी।
- 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्कजोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निमाण का कार्य वर्ष 2025–2026 में पूर्ण कर लिया गया है इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 285 बाढ़ परियोजनायें पूर्ण की गयी जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई। 11,065 किलोमीटर लम्बाई में ड्रेनों की सफाई करायी गयी।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2026–2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाये रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिये सीवरेज संबंधी कुल 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अब तक 41 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन है।

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिये 65,926 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 8 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2025–2026 में माह दिसम्बर, 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 21 घण्टे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घण्टे रही है।
- दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से माह दिसम्बर,2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये हैं। सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–2018 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये हैं।
- कृषि कार्य के लिये नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है जिन पर 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है जो कि देश में सर्वाधिक है।
- प्रदेश में दिनाँक 01 अप्रैल, 2022 से वर्ष 2025–2026 तक कुल 2,410 नये 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गयी है। साथ ही 20,924 नये वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया गया है।
- उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016–2017 में 17,890 मेगावॉट थी उसे 2025–2026 में 82 प्रतिशत बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावॉट किया गया है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2,104 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में दो गुने से अधिक है।

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति–2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2024 के अन्तर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- पी.एम.कुसुम सूर्यघर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है इस हेतु 1,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति–2022 के अन्तर्गत प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है,जो देश में सबसे अधिक है।
- ग्रीन हाईड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2024 प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 2 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नयी आवासीय योजना तथा बुन्दलशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लांच की गयी है।
- काशी–विन्ध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र का समेकित नियोजित विकास सम्भव हो सकेगा। प्रयागराज–चित्रकूट क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है।
- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत दिल्ली–गाजियाबाद– मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारम्भ हो चुका है।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मेरठ, मथुरा–वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना** हेतु 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **नई योजना–सिटी इकोनॉमिक रीजन** हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनाँक 25 दिसम्बर, 2025 को किया जा चुका है। **राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कॉर्पस फण्ड** हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास

नगर विकास हेतु लगभग 26,514 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में 14 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायतें थी। वर्ष 2017 के उपरान्त 03 नगर निगम, 04 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायतें नवगठित/उच्चीकृत की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2017 के उपरान्त प्रदेश में कुल 113 नये नगरीय निकाय गठित किये गये हैं एवं 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)–1.0 के अन्तर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 69,381 सीट सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुये सभी स्थानीय निकायों को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने में सफलता प्राप्त की है।
- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)–1.0 के अन्तर्गत मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 189 नगरीय निकायों में 1,100 ब्लॉक में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टायलेट का निर्माण कराया गया है।
- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झाँसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है।
- केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मेरठ व शाहजहाँपुर) को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है।

नागरिक उड्डयन

नागरिक उड्डयन हेतु 2,111 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर0सी0एस0) के माध्यम से की जा रही है।
- आर0सी0एस0 स्कीम को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है जिसमें आर0सी0एस0 के साथ–साथ नॉन आर0सी0एस0 उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

- जेवर एयरपोर्ट को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेन्टर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है।
- जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में पी0पी0पी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास कार्य प्रशस्त है। राज्य सरकार द्वारा जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 2 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
- जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1,100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

पिछली सरकारों के कार्यकाल में जिस प्रकार हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की घनघोर उपेक्षा की गयी, यह सर्वविदित है, पर अब स्थिति बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने अपनी सांस्कृतिक,धार्मिक धरोहरों के पुनरूत्थान का कार्य किया है जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और नये रोजगार सृजित हुये हैं।

'' ये अलग बात है तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है ।
गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आँधियों में जल रहे हैं।।''

धर्मार्थ कार्य

- श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्याधाम तक पहुँच मार्ग परियोजना के अन्तर्गत श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्याधाम मुख्य पहुंच मार्ग (रामपथ) का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है।
- जमधरा में प्रस्तावित वैदिक वेलनेस सिटी से श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर पहुँच मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
- काशी में वैदिक विज्ञान केन्द्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।
- जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जनसुविधा स्थलों को विकासित किये जाने हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीणोद्धार एवं पुनर्निमाण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

संस्कृति

- इमिलिया कोडर, बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया गया जिसका लोकार्पण किया जा चुका है।
- रामनगर, वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर आम जनता के लिये लोकार्पित किया जा चुका है।

- भारतरत्न माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के पैतृक गाँव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है।
- भारतरत्न डॉ0 बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण ऐशबाग, लखनऊ में कराया जा रहा है।
- जनपद प्रयागराज में निषादराज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गयी।

पर्यटन

- वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आये जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था तथा ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना के विकास हेतु.... करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विन्ध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु 100—100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

- ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ करने के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2,400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।
- 'एक परिवार, एक पहचान' के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। कुल 4 करोड परिवारों एवं 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आई0डी0 सृजित की जा चुकी है। प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के 32 विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को फैमिली आई0डी0 के डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिये लगभग 25,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5,544 करोड़ रूपये एवं 4,580 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन

दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारण्टी योजना के रूप में संचालित होगी।

- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–2017 से लेकर वर्ष 2025–2026 तक 36 लाख 56 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36 लाख 37 हजार आवास पूर्ण हो गये है तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिये जायेंगे। योजना हेतु 6,102 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018–2019 से लेकर वर्ष 2025–2026 तक कुल 4 लाख 61 हजार आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख 67 हजार आवास पूर्ण हो गये हैं तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिये जायेंगे।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

पंचायती राज की योजनाओं के लिये लगभग 32,090 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2020–2021 से संचालित है। योजना हेतु 2,823 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–2027 में 454 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 130 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–2027 में लगभग 57 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर का निर्माण योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

कृषि योजनाओं के लिये लगभग 10,888 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2026–2027 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है।
- एक्वाब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपीएग्रीज परियोजना में **एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विश्वस्तरीय हैंचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना** की बाह्य सहायतित परियोजना के लिये 155 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत **एग्रीएक्सपोर्ट हब** की स्थापना के लिये 245 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवाल्विंग फण्ड योजना** के लिये 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों के **डीजल पम्प सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने की योजना** हेतु 637 करोड़ 84 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संचालित है। योजना हेतु 298 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 2,400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार

- मा0 मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है।
- 76.41 करोड़ रूपये की लागत से विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में किसान एग्री मॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत रूपये 61.87 करोड़ की लागत से नवीन मण्डी स्थल चन्दौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मण्डी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उद्यान

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 7 प्रतिशत से अधिक है।

- प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु सीमान्त कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, परिवहन, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
- राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य प्रसंस्करण

- प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी एवं पशु आहार आधारित उद्योग आदि उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सुनियोजित विकास के कार्यक्रम आरम्भ कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 लागू की गयी है जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार एवं मूल्य संवर्द्धन में सहायक सिद्ध हो रही है।
- भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाईयों को पूँजीगत अनुदान देकर लाभान्वित किये जाने के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वस्तुतः चीनी मिलें व गन्ना खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। पेराई सत्र 2024–2025 में प्रदेश के 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना खेती की गयी।
- प्रदेश में संचालित 122 चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 03, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ की 23 और निजी क्षेत्र की 96 चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 09 हजार टन गन्ने की पेराई कर 92 लाख 45 हजार टन चीनी का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 8.58 लाख टन प्रतिदिन है। प्रदेश की चीनी मिलों के औद्योगिक पुनरूद्धार के क्रम में पिपराइच, मुण्डेरवां, रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गयी तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है जिससे अब तक कुल 1,25,000 टी.सी.डी. अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। मिलों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरूद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ ।

दुग्ध विकास

वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- जनपद मथुरा में पूर्व में 30 हजार लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गयी थी जिसे संशोधित करते हुये 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लान्ट के स्थापना का प्रस्ताव है जिसके लिये 23 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दुग्ध संघों में 220 नई दुग्ध समितियों के गठन

तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन का कार्य प्रस्तावित है जिसके लिये लगभग 107 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन

- प्रदेश में निराश्रित /बेसहारा पशुओं से फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गो–संरक्षण के लिये 7,497 गो–आश्रय स्थलों में 12,38,547 गोवंश संरक्षित है। इसके अतिरिक्त 155 वृहद गो–संरक्षण केन्द्र निर्माणाधीन हैं।
- माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अन्तर्गत 1,13,631 पशुपालकों को अद्यतन 1,81,418 गोवंश सुपुर्द किये गये हैं जिनको भरण पोषण हेतु दिनाँक 01 अक्टूबर, 2023 से 30 रूपये प्रतिदिन प्रति गोवंश को बढ़ाकर 50 रूपये की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है।
- छुट्टा गोवंश के रख–रखाव हेतु 2,000 करोड़ रूपये तथा वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 253 करोड़ रूपये तथा पशु चिकित्सालयों/पशु संघ केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में प्रथम बार मोबाईल वेटरेनरी यूनिट की स्थापना भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है।

मत्स्य

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष एवं महिला घटक हेतु क्रमशः 195 करोड़ रूपये तथा 115 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना हेतु 190 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार, एकीकृत एक्वा पार्क तथा मत्स्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की नई योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2025 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश इस वैश्विक आयोजन की शुरूआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना ।
- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 1539 एवं द्वितीय चरण में 1523 एम0–पैक्स चयनित की गयी हैं। योजना हेतु 32 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- ब्याज अनुदान योजना हेतु 525 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना** जिसमें दीर्घकालिक ऋण हेतु ब्याज अनुदान, सहकारी बैंक को कार्यशील पूँजी हेतु वित्तीय सहायता तथा सहकारी बैंक की शाखाओं के आधुनिकीकरण एवं ब्राडिंग हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था है, के लिये 38 करोड़ रूपये का प्रॉवधान प्रस्तावित है।
- सहकारिता क्षेत्र में **विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना** के अन्तर्गत नवीन गोदामों के निर्माण की नयी योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिये 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

- खाद्य एवं रसद की योजनाओं के लिये लगभग 20,124 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्नपूर्ति योजना हेतु 15,480 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलिण्डर रीफिलिंग योजना हेतु 1,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिये 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा के लिये 77,622 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म, स्कूल बैग, जूता–मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराये जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो–दो मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक–एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं हैं उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की नई योजना हेतु 580 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नई योजना लायी जा रही है जिसके लिये लगभग 358 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने की नई योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में अधो मानक पाये जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के लिये 22,167 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 2025–2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

- माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु 520 करोड़ रूपये तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु 10 करोड रूपये़ व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय संस्कृत पाठशाला के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल कैब क्लस्टर की स्थापना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की नई योजना हेतु 89 करोड़ रूपये से नई योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन आरम्भ किया गया है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के लिये लगभग 6,591 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक है।

- मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने की रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विन्ध्यांचल मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हेतु 50करोड़ रूपये, मुरादाबाद मण्डल में गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये तथा देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना लायी जा रही है जिसके लिये 14 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 2,365 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 23 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में है।
- राजकीय पालीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयान तथा एक्सीलेंस सेन्टर की स्थापना किये जाने लगभग 714 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है तथा 143 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों के उन्नयन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना हेतु 254 करोड़ रूपये तथा राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

व्यवसायिक शिक्षा के बजट में 2025–2026 के मुकाबले 88 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये लगभग 3,349 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है

- प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,272 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है।
- प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हैं।
- प्रदेश में 2,963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं।
- टाटा टेक्नोलॉजीज लि0 के सहयोग से फेज–1 के अन्तर्गत चयनित 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है।
- फेज–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में टाटा टेक्नोलॉजीज लि0 के सहयोग से 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य प्रगतिमान है।
- कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिये 1,000 करोड़ रूपये तथा दस्तकार प्रशिक्षण योजना हेतु लगभग 836 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रोजेक्ट प्रवीण के लिये 500 करोड़ रूपये तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल एवं युवा कल्याण

- वर्तमान में प्रदेश में कुल 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, 38 तरणताल तथा 52 जनपदों में अत्याधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना की गयी है।
- जनपद वाराणसी में पी.पी.पी. मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है।
- जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द्र राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।
- खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास, जनपद जौनपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण तथा जैतपुर रायबरेली में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण कराया जा रहा है।
- जनपद गोरखपुर में ई.पी.सी. मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वन एवं पर्यावरण

- हमारे लिये गर्व का विषय है कि देश में सर्वाधिक जैविक दबाब के बावजूद उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। राज्य को यह गौरव प्राप्त होने का मुख्य श्रेय प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे वृक्षारोपण अभियान को जाता है। वृहद वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2017 के पश्चात अब तक प्रदेश में 242 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वर्षाकाल–2026 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- सामाजिक वानिकी योजना हेतु 800 करोड़ रूपये, पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु 220 करोड़ रूपये तथा राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 189 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु लगभग 207 करोड़ रूपये तथा रानीपुर बांध फाऊण्डेशन,चित्रकूट के कॉर्पस फण्ड के गठन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा एवं ई0वेस्ट रिसाइकिलिंग एण्ड ट्रीटमेन्ट सुविधा की स्थापना कराये जाने की कार्यवाही करायी जा रही है।
- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट वर्ष 2025–2026 से 2030–2031 तक क्रियान्वित होना है। यह विश्व बैंक सहायतित मल्टीसेक्टोरल योजना है जिसके लिये 194 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सर्वसमावेशी विजन में जहाँ एक ओर अवस्थापना और उद्योगों की चिन्ता है वहीं महिलाओं, बच्चों,

श्रमिकों और समाज के दुर्बल वर्ग के कल्याण की भी चिन्ता है। प्रदेश की जनजातियों के बारे में इसके पहले कभी सोचा भी नहीं गया। यह कहने में कोई हिचक नहीं कि सदियों की रूढ़ियों को तोड़ कर समाज को नई दिशा देना एक श्रमसाध्य और समयसाध्य कार्य है, परन्तु दूरदृष्टि, दृढ़संकल्प और अहर्निश श्रम से यह सम्भव हो रहा है–

बडी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है
गम की हर शाम दबे पांव चली आती है
वक्त लगता ही नही जिन्दगी बदलने में
पर वदलने में वक्त जिन्दगी लग जाती है।

महिला एवं बाल विकास

- महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिये लगभग 18,620 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 11 प्रतिशत अधिक है।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत 2016–2017 में लाभार्थियों की संख्या 17 लाख 32 हजार थी जो 2025–2026 में अब तक 38 लाख 58 हजार 922 हो चुकी है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये 100 करोड़ रूपये तथा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रवास निर्माण योजना हेतु 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

श्रम

- ई–श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आई–डी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गयी।
- सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा–6 से कक्षा–12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र/छात्रायें इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। योजना हेतु 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समाज कल्याण

वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,953 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 67.50 लाख लाभार्थियों को रूपये 1000/– प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 8,950 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि रूपये 51,000/– से बढ़ाकर 1.01 लाख रूपये कर दी गयी है। योजना हेतु 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 950 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनजाति विकास

- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 'पीएम–जनमन' के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जा रहा है।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनाँक 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिये 3,402 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक है।

- पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 210 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजनान्तर्गत 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन के कल्याण की योजनाओं के लिये 2,140 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।

- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन को 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से धनराशि दी जा रही है। वर्ष 2017 के पूर्व यह धनराशि 300 रूपये थी। योजना हेतु 1470 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश के 07 महत्वाकांक्षी जनपदों यथा–चन्दौली, सिद्धार्थनगर, बहराईच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं हेतु 2,058 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलमेन्ट कार्यक्रम ऐसे 21 जनपदों, जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, में लागू है जिसके लिये 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्वदशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्याय

न्याय विभाग की योजनाओं हेतु लगभग 9,845 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है जो वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 9 प्रतिशत अधिक है।

- पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में अद्यतन 111 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही की गयी।
- महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थायीकरण एवं 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट एन0आई0 एक्ट के अन्तर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 05 विशेष न्यायालय/सहवर्ती पदों की निरन्तरता बढाये जाने की कार्यवाही की गयी है।

राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 18,144 आश्रित परिवार लाभान्वित हुये। वित्तीय वर्ष 2026–2027 में योजना हेतु 1,150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- एण्टी भू–माफिया अभियान के अन्तर्गत 7369 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है।
- प्रथम चरण में प्रदेश के 07 अति संवेदनशील जनपदों में 01–01 बाढ़ शरणालय बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ दिनाँक 16 जुलाई, 2025 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

परिवहन

- बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु ई0वी0 बस के लिये 400 करोड़ रूपये तथा बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री जीरों फैटलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्यवाही हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है जिसका सकारात्मक मूल्यांकन देश की शीर्षस्थ विशेष संस्थाओं–नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सी.ए.जी.द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल की सराहना सर्वत्र हो रही है–

'' काबिले तारीफ है, अंदाज एक–एक काम का।
गा रहा है गीत यू.पी., योगी जी के नाम का।।''

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 49 हजार 956 करोड़ रुपये (1,49,956 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71 हजार 278 करोड़ रुपये (71,278 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 43 हजार 802 करोड़ रुपये (43,802 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 15 हजार 808 करोड़ रुपये (15,808 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2026–2027

मान्यवर,

- प्रस्तुत बजट का आकार 09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये (9,12,696.35 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 43 हजार 565 करोड 33 लाख रुपये (43,565.33 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 08 लाख 48 हजार 233 करोड़ 18 लाख रुपये (8,48,233.18 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल प्राप्तियों में 07 लाख 28 हजार 928 करोड़ 12 लाख रुपये (7,28,928.12 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 01 लाख 19 हजार 305 करोड़ 06 लाख रुपये (1,19,305.06 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 06 लाख 03 हजार 401 करोड़ 76 लाख रुपये (6,03,401.76 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 03 लाख 34 हजार 491 करोड़ रुपये (3,34,491 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 02 लाख 68 हजार 910 करोड़ 76 लाख रुपये (2,68,910.76 करोड़ रुपये)सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय 09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये (9,12,696.35 करोड़ रुपये) है।
- कुल व्यय में 06 लाख 64 हजार 470 करोड़ 55 लाख रुपये (6,64,470.55 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 02 लाख 48 हजार 225 करोड़ 81 लाख रुपये (2,48,225.81 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 64 हजार 463 करोड़ 17 लाख रुपये (64,463.17 करोड़ रुपये)का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये)की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 54 हजार 963 करोड 17 लाख रुपये (54,963.17 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपये (96.41 करोड़ रुपये) ऋणात्मक को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 55 हजार 59 करोड़ 58 लाख रुपये (55,059.58 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 64 हजार 457 करोड़ 57 लाख रुपये (64,457.57 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 01 लाख 18 हजार 480 करोड़ 59 लाख रुपये (1,18,480.59 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।

मान्यवर,

हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहय्या कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है, उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है–

''बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिये,
बता रहा हूँ फलसफा मैं हर किसी के लिये,
पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आँसू ,
न जियें आप फकत अपनी ही खुशी के लिये।।

मान्यवर,

मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी,केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं यह बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है ।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2026–2027 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वंदे मातरम्

माघ, 22 शक संवत् 1947
तद्नुसार,
दिनाँक : 11 फरवरी, 2026